1. मॉड्यूल और इसकी संरचना का विवरण

मॉड्यूल विवरण	
विषय नाम	अर्थशास्त्र
पाठ्यक्रम का नाम	भारतीय आर्थिक विकास 01 (कक्षा XI, सेमेस्टर - 1)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था- भाग 1
मॉड्यूल Id	keec_10101
पूर्वअपेक्षित ज्ञान	औपनिवेशिक नियम, राष्ट्रीय आय, जैसे शब्दों के बारे में ज्ञान, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
उद्देश्य	इस पाठ के माध्यम से जाने के बाद, शिक्षार्थी निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे: • आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताएं • भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसितता के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या कीजिए
मुख्य शब्द	कृषि, कपास और जूट कपड़ा मिलों का व्यवसायीकरण जनांकिकीय संक्रमण, एच एंड क्राफ्ट्स, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, एल और निपटान, रेलवे, टेलीग्राफ, जमींदारी प्रथा।

2. Development Team

Role	Name	Affiliation
National MOOC Coordinator (NMC)	Prof. Amarendra P. Behera	CIET, NCERT, New Delhi
Program Coordinator	Dr. Mohd. Mamur Ali	CIET, NCERT, New Delhi
Course Coordinator (CC) / PI	Prof. Neeraja Rashmi	DESS, NCERT, New Delhi
Subject Matter Expert (SME)	Dr. Janmejoy Khuntia	School of Open Learning, University of Delhi
Review Team	Dr. Meera Malhan	DCAC, University of Delhi
Translator	Dr. Deepika Gupta	Assistant Prof., SCERT Chandigarh

विषय - सूची:

1. परिचय
2. जनांकिकीय स्थिति
3. व्यावसायिक संरचना
4. अवसंरचना
5. कृषि राज्य
6. उद्योग का राज्य
7. विदेश व्यापार राज्य
8. सारांश

परिचय

स्वतंत्रता के लगभग सात दशकों के बाद भी 1947 से 2017 के बीच, भारत अभी भी दुनिया में कम आय वाले देशों के बीच सूचीबद्ध है। भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक देश का ऐतिहासिक विकास है जो देश ने अनुभव किया है । जब अंग्रेजों ने लगभग दो सौ साल के शासन के बाद 1947 में भारत छोड़ा, तो भारत सरकार को एक अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो उनकी दूरदृष्टि का परिणाम थी। इसलिए यह ब्रिटिश सरकार के तहत होने वाले आर्थिक विकास का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। हमारा विश्लेषण भारत के आजादी समय में जनांकिकीय स्थिति, व्यावसायिक संरचना और कृषि, औद्योगिक स्थिति और विदेशी व्यापार की स्थिति बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगा।

जनांकिकीय स्थिति

किसी अर्थव्यवस्था की जनांकिकीय स्थिति का अध्ययन विभिन्न प्रमुखों जैसे जनसंख्या की वृद्धि, साक्षरता स्तर, मृत्यु दर आदि के अंतर्गत किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में गैर-समकालिक तरीके से की गई थी। लेकिन ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के बारे में विभिन्न विवरण पहली बार 1881 में एक जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए थे। कुछ सीमाओं के बावजूद, इसने भारत की जनसंख्या वृद्धि में असमानता को प्रकट किया। इसके बाद, हर दस साल में इस तरह की जनगणना की गई।

जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत के तीन चरण हैं:
चरण I, जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक हैं।
चरण II, जहाँ जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है।
चरण III, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हैं।

इसे जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत की तुलना में, यह आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि 1881-1921 के बीच, भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में वृद्धि नगण्य थी क्योंकि दोनों जन्म और मृत्यु दर बहुत अधिक थे और एक दूसरे के करीब थे। जनांकिकीय संक्रमण का दूसरा चरण 21 के बाद शुरू हुआ, जिसने जनसंख्या की उच्च वृद्धि देखी। दूसरा चरण उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से चिह्नित होता है, जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है।

1921 से 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के दौरान जनसंख्या 25 करोड़ से बढ़कर लगभग 36 करोड़ हो गई। इसलिए, स्वतंत्रता के समय भारत पहले से ही भारी जनसंख्या दबाव के खतरे में था।

साक्षरता दर और मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक विकास संकेतक भी उत्साहजनक नहीं थे। समग्र साक्षरता स्तर 16 प्रतिशत से कम था। इसमें से महिला साक्षरता का स्तर लगभग सात प्रतिशत था। समग्र मृत्यु दर बहुत अधिक थी और विशेष रूप से, शिशु मृत्यु दर काफी खतरनाक थी - 2016 में 41 प्रति हजार शिशु मृत्यु दर के विपरीत 218 प्रति हजार। जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम थी - इसके विपरीत 32 वर्ष 2016 के रूप में लगभग 69 साल। यह इंगित करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से अपर्याप्त थीं। नतीजतन, पानी और वायुजनित रोग बड़े पैमाने पर फैल गए और जीवन पर भारी असर पड़ा।

व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के वितरण को संदर्भित करती है। इसने ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत कम परिवर्तन दिखाया। कृषि क्षेत्र में कर्मचारियों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो आमतौर पर 70-75 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10 और 15-20 प्रतिशत का ही योगदान है। विभिन्न विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह देखा गया है कि उच्च स्तर के आर्थिक विकास का स्तर कृषि क्षेत्र से औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए समय के साथ कार्य बल का प्रतिशत अधिक हो जाता है। भारत के व्यावसायिक ढांचे में यह प्रवृत्ति ब्रिटिश शासन की दो शताब्दियों के दौरान गायब थी, यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था बना रहा। इसके लिए जिम्मेदार दो महत्वपूर्ण कारक हैं। एक, अंग्रेजों के आक्रमण से पहले, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग मुगल साम्राज्य और स्थानीय राजाओं और शासकों के अधीन विकसित हुए। जब अंग्रेजों ने देश पर आक्रमण किया, तो उन्होंने मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और स्थानीय राजाओं या शासकों को पराजित किया और इस तरह हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप, इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ने और कृषि को अपनी मुख्य आजीविका के रूप में अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा, भारत में ब्रिटिश प्रशासन ने इंग्लैंड में चल रहे उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किसानों को नकद भुगतान करके कृषि में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए भारत में कृषि प्रमुख व्यवसाय बना रहा।

कार्य बल के वितरण में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता भी थी। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के कुछ हिस्सों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के वर्तमान क्षेत्र शामिल थे, जिसमें कृषि क्षेत्र में एक सराहनीय वृद्धि के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिशत में गिरावट देखी गई थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। दूसरी ओर, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में उसी समय के दौरान कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई।

आधारिक संरचना

ब्रिटिश शासन का एक सकारात्मक पहलू यह है कि रेलवे, बंदरगाहों, जल परिवहन, चौकियों और टेलीग्राफ जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ था। वास्तव में 1850 में भारत में रेलवे की शुरुआत को उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। रेलवे ने राष्ट्रीय एकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई क्योंकि इसने भारत के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने और भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को

तोड़ने में सक्षम बनाया।
हालांकि, इस विकास के पीछे का असली मकसद निम्नलिखित तरीकों से विभिन्न औपनिवेशिक हितों की सेवा करना था।

1. कच्चे माल को ग्रामीण इलाकों से निकटतम बंदरगाह तक और वहां से इंग्लैंड तक ले जाने के लिए रेलवे और सड़कों की आवश्यकता थी। ये कच्चा माल, इंग्लैंड पहुंचने के बाद, तैयार माल का उत्पादन करने के लिए वहां के उद्योगों में संसाधित किया जाता था। इन सामानों को फिर भारत और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों और देशों में निर्यात किया गया। एक बार तैयार माल भारत के बंदरगाहों तक पहुंच गया, फिर इन्हें सड़क और रेलवे नेटवर्क द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों पर बिक्री के लिए ले जाया गया। ब्रिटिश माल के लिए भारत एक बड़ा बाजार बन गया। इसलिए ब्रिटिश माल के कच्चे माल और उपभोक्ता के आपूर्तिकर्ता के रूप में, भारत को "फीडर अर्थव्यवस्था" कहा जाता था।
2. जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज अन्य देशों का भी उपनिवेश करते थे जहाँ वे युद्ध लड़ते थे। इसके लिए वे हमेशा लोगों को युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना बनाने के लिए भर्ती कर रहे थे। इसलिए उनके लिए भारत के भीतर सेना को जुटाने के लिए सड़क और रेलवे नेटवर्क का निर्माण करना आवश्यक था।
3. सड़क और रेलवे नेटवर्क का उपयोग तैयार माल और अन्य वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था जहां से इन्हें अन्य कॉलोनियों और देशों में निर्यात किया जाता था। इस तरह ब्रिटिश प्रशासन ने बहुत से विदेशी मुद्रा अर्जित की।
4. ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी बुनियादी ढाँचे बनाए गए थे, भारत को इन सुविधाओं से उतना फायदा नहीं हुआ, जितनी कि उम्मीदें अपर्याप्त और सीमित थीं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर बरसात के मौसम में पहुंचने के लिए ऑलवेदर सड़कों की तीव्र कमी बनी हुई है। अधिकांश ग्रामीण भारत मुख्य धारा से कटे हुए रहे। स्वाभाविक रूप से, इसलिए, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और अकाल के दौरान शिकायतें हुईं जो ब्रिटिश काल के दौरान अक्सर होती थीं। सामाजिक लाभ, जो भारतीय लोगों को रेलवे की शुरूआत के कारण प्राप्त हुए, इस प्रकार देश के बड़े आर्थिक नुकसान से प्रभावित हुए।

सड़कों और रेलवे के अलावा, औपनिवेशिक फैलाव ने अंतर्देशीय व्यापार और समुद्री लेन के विकास के लिए भी उपाय किए। हालाँकि, ये उपाय संतोषजनक नहीं थे। अंतर्देशीय जलमार्ग, कई बार, गैर-आर्थिक भी साबित हुए। उदाहरण के लिए, उड़ीसा तट पर तट नहर का मामला लें। यद्यपि सरकारी खजाने को भारी कीमत पर नहर का निर्माण किया गया था, लेकिन इसका उपयोग बहुत सीमित या गैर-मौजूद था। मुख्य कारण यह है कि यह रेलवे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहा, जिसने जल्द ही नहर के समानांतर चलने वाले क्षेत्र का पता लगाया। इसलिए परियोजना को अंततः छोड़ दिया गया था।

भारत में अंग्रेजों द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक और महत्वपूर्ण विकास टेलीग्राफ की शुरुआत के माध्यम से दूरसंचार प्रणाली की स्थापना थी। 1850 में, कलकत्ता (अब कोलकाता) और डायमंड हार्बर के बीच पहली प्रयोगात्मक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। 1851 में, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उपयोग के लिए खोला गया था। 1853 में भारत के कुछ हिस्सों को टेलीग्राफ लाइनों के माध्यम से जोड़ा गया था जिसमें कोलकाता (तब कलकत्ता) और पेशावर, आगरा, मुंबई (तब बॉम्बे) और चेन्नई (तब मद्रास) शामिल थे। 1854 में जनता को टेलीग्राफ की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अलग विभाग

खोला गया। देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा 1881 में स्थापित की गई थी, जब इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को सरकार द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। भले ही इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा एक महत्वपूर्ण विकास थी, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। वास्तव में, एक उपयोगी सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा के बावजूद, दोनों टेलीग्राफ और डाक सेवाएं अपर्याप्त के माध्यम से बनी रहीं।

कृषि की स्थिति

ब्रिटिश के भारत आने से पहले, देश में कृषि की स्थिति बहुत संतोषजनक थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के अनुसार, बंगाल में नेविगेशन और सिंचाई के लिए गंगा से निकलने वाली नहरों की अंतहीन संख्या थी, जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं, सब्जियां, अनाज, फव्वारे, बत्तख और कलहंस पैदा करते थे। यह निर्यात, बहुतायत में, कॉटन और सिल्क्स, चावल, चीनी और मक्खन में भी होता है। इसमें सूअरों के झुंड, भेड़ और बकरियों के झुंड और हर तरह की मछलियाँ थीं। बर्नियर के अनुसार, बंगाल मिस्र से भी अधिक समृद्ध था।

हालांकि, इसके विपरीत भारतीय कृषि ब्रिटिश शासन के तहत ठहराव से ग्रस्त थी। खेती के तहत क्षेत्र के विस्तार के कारण उत्पादन में कुछ सुधार के अलावा, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम रही। कई कारक इसके लिए जिम्मेदार थे। एक, शहरी क्षेत्रों में हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश ने लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बसने और कृषि को प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए मजबूर किया। दूसरा, इंग्लैंड में उद्योगों को भारत से कच्चे माल की आवश्यकता होती है जैसे इंडिगो, कपास इत्यादि। इसके लिए ब्रिटिश एजेंट किसानों से इन कच्चे माल को नकद भुगतान करके खरीदते थे। इसलिए, नकदी से आकर्षित होकर किसानों ने इन फसलों की खेती शुरू की। खाद्यान्न उत्पादन से संसाधनों को स्थानांतरित करना। नकदी के लिए फसलों के इस विकास को " भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण कहा जाता है"। तीसरा, इन दोनों कारकों ने इस क्षेत्र के आधार पर 85 प्रतिशत आबादी के साथ कृषि पर भारी जनसंख्या दबाव बनाया। स्वतंत्रता के समय यह आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत था जो अभी भी बहुत अधिक था। भारी जनसंख्या दबाव बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार था। चौथा, औपनिवेशिक सरकार ने भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए बंगाल प्रेसीडेंसी में जमींदारी प्रथा की जमींदारी प्रथा शुरू की। देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के अन्य निपटान शुरू किए गए थे। इन जमींदारों को राजस्व की एक निश्चित राशि जमा करने और जमा करने के लिए कहा गया था जो उन्हें अपनी स्थिति खो देने के लिए थी। इसलिए, जमींदारों ने गरीब किसानों के विकास के लिए काम करने के बजाय राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बल के उपयोग सहित अपने सभी प्रयास किए। पांचवा, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं की कमी और उर्वरकों के नगण्य उपयोग, सभी ने किसानों की दुर्दशा को बढ़ा दिया और कृषि उत्पादकता के निम्न स्तर पर योगदान दिया। छठवाँ अविभाजित देश की अत्यधिक सिंचित और उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। भारत का जूट उद्योग, जो उस समय विश्व बाजार में एकाधिकार का आनंद लेता था, जब से लगभग पूरा जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) का हिस्सा बन गया था।

उद्योग की स्थिति

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ आधुनिक उद्योग सामने आए। प्रारंभ में, यह विकास कपास और जूट कपड़ा मिलों की स्थापना तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें ज्यादातर देश के पश्चिमी हिस्सों, अर्थात् महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित थीं, जबकि जूट मिलें मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित थीं। जबकि कपास मिलों का स्वामित्व ज्यादातर भारतीयों के पास था, जूट मिलों का स्वामित्व ज्यादातर विदेशी स्वामित्व में था। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण विकास बीसवीं सदी की शुरुआत में हुआ था, जब 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) को शामिल किया गया था। चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ अन्य उद्योग भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने आए।

हालांकि, भारत में आगे औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए मशीन टूल्स के निर्माण के रूप में शायद ही कोई पूंजीगत सामान उद्योग था। इसलिए, कृषि की तरह, भारत ने अपने औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए अच्छा नहीं किया। जैसा कि पहले कहा गया था ब्रिटिशों के आगमन ने आंतरिक युद्धों के कारण हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया। इसने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा की और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ने और कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए मजबूर किया जिसने बदले में कृषि पर भारी बोझ बनाया। यहां कुछ विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के इस थोक विस्थापन का कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा, नए औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान बहुत कम रहा। तथ्य यह है कि औपनिवेशिक नीति भारत में औद्योगीकरण के खिलाफ दो विशिष्ट कारणों से हुई। एक, ब्रिटेन में आगामी आधुनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के मात्र निर्यातक की स्थिति को कम करने के लिए और दो, उन उद्योगों के तैयार उत्पादों के लिए भारत को एक विशाल बाजार में बदलने के लिए।

विदेशी व्यापार की स्थिति

कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित परिस्थितियों ने देश के विदेशी व्यापार को प्रभावित किया। कृषि के व्यावसायीकरण ने भारत को कच्चे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, इंडिगो, जूट आदि जैसे प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बनने के लिए मजबूर कर दिया। निर्यात का मुख्य स्थान इंग्लैंड हुआ जहां उद्योगों ने इन कच्चे माल का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और उन्हें निर्यात करने के लिए किया। चूंकि भारत में तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त उद्योग नहीं थे, इसलिए यह कपास, रेशम और ऊनी कपड़ों और हल्की मशीनरी के रूप में पूंजीगत वस्तुओं जैसे ब्रिटेन के सामान का आयातक बन गया। इसलिए सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, ब्रिटेन ने भारत के निर्यात और आयात पर एकाधिकार बनाए रखा। यह पाया गया कि भारत के आधे से अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटेन ओ एन एल वाई तक सीमित थे। 1869 में स्वेज नहर के उद्घाटन ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और तेज कर दिया। भले ही भारत निर्यात अधिशेष उत्पन्न कर सकता था, लेकिन शायद ही सोने या विदेशी मुद्रा की कोई आमद हुई हो, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अधिशेष का उपयोग ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यालय द्वारा किए गए खर्चों के भुगतान के लिए किया गया था, युद्धों पर खर्च उपनिवेशवाद, और अदृश्य वस्तुओं के आयात को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश सरकार द्वारा। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के धन को बाहर निकालने के लिए विदेशी व्यापार का इस्तेमाल किया।

जिन अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे उनमें चीन, सीलोन (श्रीलंका) और फारस (ईरान) शामिल थे।

निष्कर्ष

भारत पहले ही उच्च जनसंख्या वृद्धि के साथ **1921** की जनगणना से शुरू हुए जनांकिकीय संक्रमण के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। शैक्षिक उपलब्धियों और स्वास्थ्य देखभाल से संकेतिक जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब थी। जबकि **84** प्रतिशत आबादी अनपढ़ थी, लेकिन जीवन प्रत्याशा **32** साल के बराबर थी। शिशु मृत्यु दर खतरनाक रूप से **281** प्रति हजार पर उच्च थी। रेलवे का निर्माण ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारत को दिया गया एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। हालाँकि, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की तुलना में औपनिवेशिक हित की सेवा के लिए कच्चे माल और सेना का परिवहन करना था। भारत की कुल कार्यशक्ति का लगभग तीन चौथाई हिस्सा कृषि पर निर्भर था और इस तरह देश प्राथमिक उत्पादन और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ था। भारतीय कृषि को भारी जनसंख्या दबाव, जमींदारी प्रथा के प्रसार और व्यावसायीकरण के कारण नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटेन भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना रहा और भारत के धन को बाहर निकालने के लिए विदेशी व्यापार का शोषण किया।